Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2022 International Council for Education Research and Training
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
ISSN: 2959-1376
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत

रिंकू

सहायक प्राध्यापक, रक्षा अध्ययन विभाग, ज्योतिबा फुले राजकीय महाविद्यालय रादौर, यमुनानगर

सारांश

मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है। इस अभियान के तहत भारत के रक्षा क्षेत्र में शामिल होने के लिए पूरे विश्व से लगभग 500 करोड रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। 2020 में रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा जो कि पहले 49 प्रतिशत था बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया। कुछ मामलों में यह निवेश 100 प्रतिशत तक भी है। जब यह अधिसूचना जारी हुई तो विदेशी शक्तियों का रुझान भारत की तरफ बढ़ा। अब तक भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत सैन्य हथियार बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को टॉप 100 कंपनियों में शामिल किया गया। इसका वर्तमान उदाहरण भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला युद्ध पोत विक्रांत है जोकि 75 प्रतिशत स्वदेशी निर्माताओं द्वारा बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग 13 साल का समय लगा। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत आने वाले समय में रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा आयातक ही नहीं निर्यातक भी बनेगा।

मुख्य शब्द: *रक्षा क्षेत्र, भारत, विदेशी निवेश।*

प्रस्तावना

वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना तेजी से पनप रही है। यही बात भारत पर भी लागू होती है। भारत के पाकिस्तान से संबंध किसी से छिपे नहीं है। दूसरी तरफ चीन के संबंध भी भारत के साथ दिन प्रतिदिन कटु होते जा रहे हैं। यही कारण है कि 'लोकल फॉर वोकल' का नारा बुलंद किया गयज्ञं कोरोन काल में सभी ने देखा कि जो देश अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं अक्सर समय पर उन्हें आपूर्ति नहीं मिल पाती और काम बीच में ही रह जाता है। अब यह साफ है कि निजी क्षेत्र को रक्षा के क्षेत्र में अपने कदम जमाने चाहिए। तभी भारत की अन्य देशों से निर्भरता को खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि 2025 तक भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की योजना बनाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय अब रक्षा

@2022 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

उत्पादन के क्षेत्र में स्वदेशी निर्माताओं को बड़ा प्रोत्साहन देने की तैयारी में लगा हुआ है। अभी तक देश तत्कालिक रक्षा उत्पादन को खरीद कर आपूर्ति करने की कोशिश में था, परंतु अब भारत सरकार दीर्घकालिक रणनीति बना रही है ताकि देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत के पाकिस्तान तथा चीन के साथ रिश्तो को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2025 तक रक्षा सामग्री पर 1.75 लाख करोड़ रुपए (25 अरब डॉलर) खर्च करेगा। अभी तक भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इजरायल आदि देशों पर निर्भर रहा है। 2019 के बीच भारत ने सऊदी अरब से भी ज्यादा हथियारों की खरीद की है परंतु फिर भी कैग की रिपोर्ट के अनुसार सेना के पास अभी भी हथियारों की कमी बनी हुई है। फ्रांस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों की खेप भारत आ चुकी है । जहां भारत में अत्याधुनिक राकेट, मिसाइल, उपग्रह तथा कार्योजनिक इंजन तक का निर्माण हो चुका है। रक्षा संबंधी हथियार विकसित करने में भी भारत सफल होगा।

रक्षा संबंधी मामलों का इतिहास

भारतीय रक्षा के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय रक्षा उद्योग 200 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है रक्षा व्यवस्था का इतिहास और विकास ब्रिटिश राज से भी जुड़ा हुआ है।1801 में पहली गन कैरिज एजेंसी की स्थापना की गई। देश की आजादी के समय 18 कारखानों की स्थापना की गई थी जो आज बढ़कर 200 से भी अधिक हो गई है। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपना रक्षा व्यय बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत किया। 1965 के भारत-पाक युद्ध में अमेरिका ने हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया । जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के सोवियत संघ से संबंध मजबूत हुए । धीरे-धीरे भारत की सोवियत संघ पर निर्भरता बढ़ने लगी। यही कारण था कि भारत ने रक्षा औद्योगिकरण के दृष्टिकोण को लाइसेंस आधारित उत्पाद से स्वदेशी डिजाइन आधारित उत्पाद में बदलने पर मजबूर होना पड़ा। 1980 में सरकार ने डीआरडीओ को हाई प्रोफाइल बनाना शुरू किया। रक्षा समीकरण में सबसे प्रासंगिक विकास 1983 में किया गया, जब सरकार ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को स्वीकृत किया। 1990 में एपीजे अब्दुल कलाम की स्व रिलायंस समीक्षा समिति ने एक 10 वर्षीय आत्मनिर्भर योजना तैयार की जिसमें एक आत्मनिर्भर सूचकांक का प्रस्ताव रखा। 1998 में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करने पर समझौता हुआ। सन 2000 में हम ज्यादातर हथियारों का आयात करते थे। डीआरडीओ एकमात्र ऐसा संगठन था जो रक्षा के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर पाता था। वर्ष 2001 में सरकार ने 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति दी। अनुमति के बाद भी निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू के तीन-चार सालों में ना के बराबर थी। सन 2014 में सरकार ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त परिवर्तन किए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

@2022 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

को रक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाने लगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत 2014-15 में प्रमुख हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था और वैश्विक कुल संपत्ति का 9.5 प्रतिशत हिस्सा था। तब से भारत के सैन्य खर्च में 3.1 प्रतिशत भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत रक्षा पर खर्च कर रहा है।

मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत:माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि भारत को महत्वपूर्ण निवेश का स्थान बनाया जा सके। मेक इन इंडिया क्रांतिकारी विचार है जिसका अर्थ है नवाचार को बढ़ावा देना।किसी भी देश को बाहरी हमलों से बचाने और देश के नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए रक्षा क्षेत्र का मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण है। साल 2014 से 2021 तक भारत ने भी रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न बदलाव किए हैं। इन्हीं का परिणाम है कि आज भारत के रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक असर दिखने लगा है। साथ ही रक्षा नीतियां में भी जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे, उनका सकारात्मक परिणाम भी सामने हैं।

हाल ही में "सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्यूफैक्चर्रस" के सालाना सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारतीय रक्षा उद्योगों को घरेलू रक्षा मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ साल में सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत सुधारों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका असर व्यापार व्यवस्था, संचार, राजनीतिक और सैन्य शक्ति पर स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं, उससे सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है और भारतीय उद्योग को उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।"

रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े सुधार:

"7 जून 2020" का वह दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता जब रक्षा क्षेत्र में एक साथ कई ऐतिहासिक बदलाव किए गए थे। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 रक्षा सुधारों पर एक ई-बुक जारी की थी। यह ई-बुक वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए रक्षा सुधारों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ और सैन्य मामलों के विभाग:

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का निर्माण सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में से एक था।जनरल बिपिन रावत को पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्होंने सचिव, डीएमए की जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। सीडीएस का पद सशस्त्र बलों के बीच दक्षता और समन्वय बढ़ाने और दोहराव को कम करने के लिए बनाया गया था, जबकि डी एम ए की स्थापना बेहतर नागरिक-सैन्य एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:

@2022 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए, 101 रक्षा वस्तुओं की एक सूची, जिसके लिए आयात पर प्रतिबंध होगा, अगस्त 2020 में अधिसूचित की गई थी। 2020-21 में बीते वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत बजट वृद्धि की गई थी।

रक्षा निर्यात में वृद्धि:

निजी क्षेत्र के साथ बढ़ी हुई भागीदारी से रक्षा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई। कुल रक्षा निर्यात का मूल्य 2014-15 में 1,941 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 9,116 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा, भारत पहली बार रक्षा उपकरण निर्यातक देशों की सूची में शामिल हुआ, क्योंकि भारत के रक्षा उपकरणों का निर्यात 84 से अधिक देशों में विस्तारित हुआ।

रक्षा अधिग्रहण:

पहले पांच राफेल लड़ाकू विमान जुलाई 2020 में भारत पहुंचे और इसके बाद और आए जिन्होंने भारतीय वायु सेना के शस्त्रागार की मारक क्षमता को बढ़ाया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सुधार:

युवाओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु, 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं शुरू की गईं। डीआरडीओ ने डिजाइन और विकास में निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाया और उद्योग के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए 108 सिस्टम और सब सिस्टम की पहचान की।

बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती:

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के भीतर प्रक्रियाओं और कार्यप्रवाह में सुधारों ने इसे कुछ मामलों में समय से पहले लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाया। लेह-मनाली राजमार्ग पर रोहतांग में 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी "अटल टनल" का उद्घाटन किया गया।

सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी:

शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना की दस शाखाएं खोली गईं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से सभी सैनिक स्कूल छात्राओं के लिए खोल दिए गए।

कोविड-19 के दौरान नागरिक प्रशासन को सहायता:

रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डीआरडीओ ने राज्यों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए कई अस्पतालों की स्थापना की। इसके अलावा कोविड से संबंधित दवाओं और उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता भी प्रदान की।

सीमाओं से परे मदद:

सशस्त्र बलों ने संकटग्रस्त देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस क्रम में भारतीय नौसेना ने 2020-21 के दौरान आठ राहत मिशन चलाए।"वंदे भारत मिशन" के तहत ईरान, श्रीलंका और मालदीव से फंसे

@2022 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

भारतीयों को निकालने के अलावा, भारतीय नौसेना के जहाजों ने पांच देशों को कोविड-19 चिकित्सा राहत प्रदान की गई। आईएनएस ऐरावत ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को 270 मीट्रिक टन खाद्य सहायता पहुंचाई।श्रीलंका के तट को उसके सबसे बड़े तेल रिसाव से बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने बचाव अभियान का नेतृत्व किया।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता:

2025 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर, महाशक्ति की महत्वाकांक्षा, पड़ोस में सुरक्षा चुनौतियों की बढ़ती जटिलताओं और आर्थिक शक्ति जैसे हितों की रक्षा हेतु भारत को मजबूत रक्षा क्षमताओं की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में, पिछले एक दशक में, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक रहा है। वैश्विक हथियारों के आयात का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत ने आयात किया। हालांकि, हथियारों, पुर्जों और गोला-बारूद के लिए 60-70 प्रतिशत आयात-निर्भरता के साथ सैन्य संकट के दौरान कमजोरियां पैदा होती हैं। इसे समझते हुए ही भारत ने अब देश के भीतर ही इन अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण को बढ़ावा दिया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत कई उपायों की घोषणा की है। सरकार का यह कदम सही दिशा में हैं। वास्तव में भारत को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक प्रकार से लंबित सुधार के रूप में है।

आत्म निर्भर अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार:

1.एफडीआई निवेश में संशोधन: स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है।

2. परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू): सरकार से एक परियोजना प्रबंधन इकाई (अनुबंध प्रबंधन उद्देश्यों के लिए) की स्थापना करके समयबद्ध रक्षा खरीद और तेजी से निर्णय लेने की शुरुआत की उम्मीद है।

3. रक्षा आयात में कमी: सरकार आयात के लिए प्रतिबंधित हथियारों-प्लेटफार्मों की एक अधिसूचित करेगी और इस प्रकार ऐसी वस्तुओं को केवल घरेलू बाजार से ही खरीदा जा सकता है।

4. घरेलू पूंजी खरीद के लिए अलग बजट का प्रावधान।

5.आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण: इसमें कुछ इकाइयों की सार्वजनिक सूची शामिल होगी, जो डिजाइनर और अंतिम उपयोगकर्ता के साथ निर्माता के अधिक कुशल इंटरफेस को सुनिश्चित करेगा।

मेक इन इंडिया" से "मेक फोर वर्ल्ड" की ओर

भारत अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए मेक फोर वर्ल्ड की ओर अग्रसर है। यह काबिले तारीफ है कि अब भारत में बन रहे रक्षा उपकरणों को विदेश में खरीदा जा रहा है। इसी के बलबूते भारत पहली बार रक्षा उपकरण निर्यातक देशों की सूची में शामिल हुआ है। इसी के साथ भारत के रक्षा

@2022 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

उपकरणों का निर्यात 84 से अधिक देशों में विस्तारित हुआ है।

रक्षा क्षेत्र में भारत ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है। इससे निजी क्षेत्र के साथ बढ़ी हुई भागीदारी से रक्षा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 2014 के 1330 करोड़ के विदेशी निवेश से बढ़कर अब यह 2871 करोड़ के करीब पहुंच चुका है।

भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का नतीजा ही है कि आज भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात उम्मीद से भी अधिक बढ़ गया है। कुल रक्षा निर्यात का मूल्य 2014-15 में 1,941 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 9,116 करोड़ रुपए हो गया।

रक्षा अधिग्रहण में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता

पिछले 10 वर्षों में आधुनिकीकरण की दिशा में सबसे अधिक जोर देते हुए बीते वर्ष की तुलना में 2020-21 में 10 प्रतिशत बजट वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई पारदर्शिता के लिए नीतिगत सुधारों में सितंबर 2020 में नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करना और अक्टूबर 2020 में डीआरडीओ खरीद नियमावली में संशोधन करना शामिल था। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, बाय इंडियन-आईडीडीएम के रूप में खरीद के लिए प्रावधान शुरू किया गया, जबकि पहली बार नॉन-मिशन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए लीजिंग की शुरुआत की गई थी।

निष्कर्ष

बीते साल जहां देश ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के मोर्चे पर लंबी छलांग लगायी जिससे सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ी, वहीं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं के एकीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की गयी।विमानवाहक पोत से लेकर , लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, पनडुब्बी , मिसाइल , असाल्ट राइफल , तोप, राकेट , अत्याधुनिक राडार प्रणाली,हवाई पट्टी रोधी हथियार और अनेक महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद अब देश में ही बनाये जा रहे हैं।आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेक इन इंडिया से आगे मेक फॉर वर्ल्ड की नीति पर चलते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक पैंतीस हजार करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर में भारत में बनी बुलेटप्रूफ जैकेट की मांग है। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेटप्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू कर रहा है विक्रांत का जलावतरण रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जिसका 75 प्रतिशत निर्माण भारत में ही किया गया है अतः हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी के साथ आत्मनिर्भर राष्ट्र बन कर उभरेगा।

संदर्भ सूची:

@2022 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2022, Vol. 01, Issue 01, 82-88
https://doi.org/10.5281/zenodo.7747872

1.https://www.jagran.com/news/national-make-in-india-indias-self-reliance-increased-in-the-defense-sector-foreign-investment-of-crores-was-received-for-making-weapons-22924668.html

2.https://patheykan.com/

3. https://www.amarujala.com/india-news/know-the-history-of-indian-ordnance-factories-and-its-importance

4.https://govtvacancy.net/sarkari-job/bharataya-rakashha-kashhatara-ka-savathashakaranae-indigenisation-of-indian-defence-sector-in-hindi-2

5.https://pibindia.wordpress.com/2017/08/01/

6.https://newsonair.com/hindi/2021/10/03/know-how-much-improvement-in-the-countrys-defense-sector-from-2014-to-2021/

7.https://www.punjabkesari.in/national/news/india-took-a-giant-leap-in-self-reliance-in-the-defense-sector-1518528

8.https://www.jansatta.com/politics/india-used-to-import-most-of-the-defense-equipment-at-one-time-but-now-it-has-come-to-play-a-big-role-of-exporter-in-defense-sector/1659268/

9.https://www.performindia.com/india-towards-self-reliance-in-the-defense-sector/